

## विचार बिन्दु

इतिहास के तजुर्बाँ से हम सबक नहीं लेते, इसीलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। –विनोबा

## गणतंत्र में गण, गौण

नीतीश कुमार ने एक बार पुनः महागठबंधन से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सरकार बनाई और नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले साल 2000 में वे मुख्यमंत्री बने थे किंतु बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उन्हें 7 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा था। 2005 से 2013 तक भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। 2014 में जब प्रधान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी द्वारा बनाया गया तो उन्होंने एन.डी. से नाता तोड़कर दिया और मांजी को मुख्यमंत्री बनवाया। 2015 में मांजी को हटाकर खुद गठबंधन के माध्यम से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। इसके बाद, चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2017 में इन्होंने फिर राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ लिया और एनडीए में लौटकर बनाई एवं मुख्यमंत्री बने। 2020 का चुनाव भी उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा और बहुमत प्राप्त किया, किंतु 2022 में फिर एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन से जुड़ कर मुख्यमंत्री बने। अब, 28 जनवरी को एक बार फिर महा गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने प्रातः काल इस्तीफा दिया और शाम को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री पद पर उनकी यह नौवीं बार शपथ थी।

विडंबना यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपना दल बदल करने से रोकने के लिए तो दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है, किंतु पूरा दल ही यदि किसी एक विचारधारा के संगठन के स्थान पर दूसरे के साथ गठबंधन कर ले तो उसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। उस दल की न तो मान्यता समाप्त होती है एवं न ही उसके सदस्यों को सदस्यता समाप्त होती है। नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व ही जनता दल (यू) के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे एवं इस कारण उनके पास इस दल के बारे में निर्णय करने की शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई थीं।

संसद और विधानसभाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा दल बदल को घटनाएँ बहुत बढ़ने लगीं तो उन पर नियंत्रण करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। जब यह भी दल बदल को रोकने में अधिक प्रभावी नहीं हुआ तो यह शर्त लगाई गई कि किसी भी दल के निर्वाचित विधायकों या सांसदों में से न्यूनमत दो तिहाई दल बदल करें तब ही उनकी सदस्यता बची रहेगी अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

नीतीश कुमार ने जो किया है उसे रोकने का कोई कानून नहीं है। जिस विचारधारा से सहमत होते हुए मतदाता ने जनता दल (यू) को जितायी था, यदि वही अगले चुनाव से पूर्व किसी और के साथ गठबंधन कर ले तो, इसे मतदाताओं के साथ एक प्रकार से धोखा ही कहा जा सकता है। हद तो तब हो गई, जब 2005 के बाद तीन बार नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस से समझौता किया और तीन बार उसे तोड़ा तथा भारतीय जनता पार्टी और एन डी ए के साथ समझौता किया। यही पता नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? शापद यही कि वे किसी न किसी प्रकार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। क्या किसी व्यक्ति की महत्वकांक्षा इतनी अधिक हो सकती है कि वह सारे सिद्धांतों को तिलांजलि देकर हर दो-तीन वर्षों में अपनी प्रतिबद्धता को बदलता रहे?

नीतीश कुमार जब प्रारंभ में सत्ता में आए थे तो उनके काम के कारण उनकी 'पहचान 'सुशासन बाबू' के रूप में बनी थी। पहली बार यह लगा कि बिहार में लालू यादव के समय का जंगल राज समाप्त होने को है। उन्होंने नृपि नीतीश कुमार और निम्बत्ता के साथ शहाबुद्दीन जैसे कई बाहुबलियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की और उन्हें जेल भिजवाया। जो ख्याति नीतीश कुमार ने अच्छा काम करके प्रारंभिक नौ वर्षों (2005 से 2013) में अर्जित की और बिहार को राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया, वह हाल के कुछ सालों में धूल धुसरित हो गई है। हाल ही में महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय तो अविश्वसनीय ही कहा जा सकता है।

जब 2013 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़ा था तब से, वे निरंतर नरेंद्र मोदी और भाजपा को आलोचना करने से नहीं थकते थे। 2016 में इन्होंने फिर एन डी ए के साथ गठबंधन किया और लालू यादव एवं उनके नेताओं को भी घर के कोसना प्रारंभ कर दिया। 2019 में लोक सभा का चुनाव एन डी ए के साथ लड़ा और 40 में से 39 सीटों पर विजय प्राप्त की। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के साथ आए और सत्ता प्राप्त की।

2022 में इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री बने रहे। हाल ही में फिर 2024 में बीजेपी के साथ आ गए और गठबंधन को छोड़ दिया।

जो प्रयास विपक्ष दलों की एकता का 'इंडिया' गठबंधन बनाकर किया जा रहा था उसमें प्रमुख भूमिका नीतीश कुमार की ही थी। उनके इस आवरण से यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि राजनीति में शुचितता और नैतिकता का कोई स्थान शेष नहीं है। यहाँ सर्वोपरि है, स्वयं का सत्ता में बने रहना। दलों के अंदर तो व्यक्तियों का संघर्ष दबा गया है किंतु पूरे के पूरे दल द्वारा किसी का साथ छोड़कर जाने का प्रयास भी हो रहा है।

दूसरे के साथ मिलने की जो कार्रवाई अभी की है, वैसा उदाहरण बहुत नहीं देखने को मिलता है। कैसे किसी की अंतरात्मा गवाही दे सकती है कि कल तक जिसको कोस रहे हों, और विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हों, आज उन्हीं के साथ मंच साझा करके चुनाव प्रचार करें और जिनके साथ अब तक सरकार चला रहे थे, उन्हीं को बड़ा बुरा करना प्रारंभ कर दें।

संयोग से नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने का काम भी तभी किया गया जब 2 दिन पूर्व ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि इस दिन भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। गणतंत्र का अर्थ ही यह है कि जनसाधारण की सत्ता सर्वोच्च है।

आजकल जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसमें जनसाधारण की भूमिका केवल पांच साल में एक बार वोट देने तक सीमित हो गई। जो लोग चुने जाते हैं, वे सिद्धांतों को तर्क में रखकर अवसरवादिता की पराकाष्ठा करते हुए पाला बदलते रहते हैं। ऐसा करके हम गणतंत्र की धारणा को ही नकारने की बात कर रहे हैं।

समय आ गया है, जब ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें एक बार कोई दल किसी दल/गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए और यदि वह अगले चुनाव से पूर्व ही किसी अन्य दल के साथ मिल जाने तो उसकी मान्यता निलंबित रहे अथवा उस दल के सभी निर्वाचित सदस्यों को सदस्यता समाप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नेतागण गिरगिट की तरह रंग बदलते ही रहेंगे यानि पाला बदलते रहेंगे।

ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार न इधर के रहेंगे ना उधर के और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हाशिये पर धकेल देगी। इस प्रकार के नेताओं को सबक सिखाने का काम केवल जनता ही कर सकती है। अब उसे यह अधिकार काम में लेना ही चाहिए।

नीतीश कुमार की बार-बार पाला बदलने की प्रवृत्ति को बहाल देने में भारतीय जनता पार्टी एवं उनके नेताओं ने भी पूरा सहयोग किया है और उसका भी उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। जो नीतीश कुमार, मोदी समेत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक मंच से कोष रहे थे, अब उन्हीं से समझौता करके अपने साथ पास में मंच पर बिठाकर कैसा अनुभव भाजपा के नेताओं को होता होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लगता है, राजनीति में अब किसी भी प्रकार की सिद्धांति का मत करना बेमानी हो गया है।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग मतदाताओं के समर्थन से सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है तो इसका दायित्व अब साधारण मतदाता को अपने हाथ में लेना होगा और सबक सिखाना होगा ऐसा नेताओं को, जो उनके साथ समय-समय पर विश्वास घात करते हुए पाला बदलने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

पाठकों को शायद पता हो कि गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा राष्ट्र, जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित है।

नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व तीन बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुके हैं और तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके थे। नीतीश कुमार के बार-बार गठबंधन को रद्द करने से उनकी छवि को निश्चित रूप से धक्का लगा है। वह इंडिया ब्रॉक या विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक के रूप में भूमिका निभा रहे थे और रातों रात इन्होंने एन डी ए से समझौता कर लिया। देश में ऐसा कोई भी नेता शायद नहीं होगा जिसने 9 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली होगी। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने जिस दल के साथ गठबंधन किया उसे तीन बार तोड़ कर पुनः उसके साथ समझौता किया हो। नीतीश कुमार का यह कृत्य देश की राजनीति में काले अश्वत्थ के रूप में ही देखा जाएगा।

आशा की जाना चाहिए कि बार बार पाला बदलने की यह अनिष्ट घटना ही होगी। आगामी चुनावों में नीतीश कुमार को बुरी तरह परख करके ही यह संदेश दिया जा सकता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं को पसंद नहीं किया जाता। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को तेजी से रंग बदलते देखकर तो गिरगिट की भी शर्म आ जाए।

–अतिथि सम्पादक,  
राजेन्द्र भागवत  
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

## हमारी परीक्षा प्रणाली – दशा और दशा



प्रो. अशोक कुमार

भारत म लगभग 1,100 स आधक विश्वविद्यालय, 50,000 संबद्ध कॉलेज और 60 स्कूल बोर्ड हैं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 40.15 मिलियन छात्र हैं। (एआईएसएचई रिपोर्ट 2020-21) नियोजता उम्मीदवारों की शैक्षणिक उपलब्धियों और रोजगार के लिए उपयुक्तता का कठोर मूल्यांकन करते हैं।

परीक्षाएँ छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे न केवल विषय के ज्ञान और समझ का परीक्षण करते हैं बल्कि छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में भी मदद करते हैं। परीक्षा के माध्यम से, छात्र अवधारणाओं को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और विषय वस्तु की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है क्योंकि अब परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन नहीं बल्कि प्रमाण पत्र प्राप्त करना रह गया है। यह मुख्य रूप से जीविका चलाने और नौकरी पाने का एक साधन हो गई है सम्पूर्ण ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है स्मरण शक्ति पर एकमात्र बल दिया जाता है !

क्या छात्रों को अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट करने और उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए प्रयोग आयोजित करना पवित्र है? क्या छात्रों को अन्य प्रणाली या माध्यम से प्रमोट और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता?

परीक्षा के नाम पर न जाने कितने शैक्षणिक दिन बर्बाद कर दिये जाते हैं। दोनों पक्षों की बहुत सारी ऊर्जा छात्रों द्वारा पेपर लिखने और शिक्षकों द्वारा उनकी जाँच और मूल्यांकन करने में खर्च होती है, जो या तो शिक्षकों द्वारा सिखाई गई एक ही चीज होती है या इंटरनेट से चुराई गई होती है। दोनों ही मामलों में, छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर उनके अपने नहीं, किसी और के हैं, तो शिक्षक किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? परीक्षाओं का आधार क्या है? आज परीक्षा में नकल एक वैश्विक समस्या है और इसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालयों के साथ हित उलझे हुए हैं।

परीक्षा प्रणाली अब पुरानी और जर्जर हो चुकी है। कुछ नया होना चाहिए और सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक समग्र तरीके अपनाए जाने चाहिए।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कई खामियाँ हैं, जो छात्रों की शिक्षा और कौशल के वास्तविक मूल्यांकन में बाधा डालती हैं। परीक्षा प्रणाली के अत्यधिक औपचारिकीकरण के परिणामस्वरूप विनाश हुआ है। प्रश्न पैटर्न, अर्थात्, मूल्यांकन के मामले में एकरूपता को लेकर अत्यधिक जुनून बीते दिनों के अवशेष है। सभी विषय अपनी प्रकृति में भिन्न हैं और मूल्यांकन के लिए अलग-अलग मानदंडों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा सिस्टम सभी के लिए एक ही आकार में विश्वास रखता है। यह

हास्यास्पद है!

परीक्षाओं को नियमित और निरंतर बनाना चाहिए। इससे छात्रों को अपनी सीखने की प्रगति पर लगातार नज़र रखने में मदद मिलेगी।

परीक्षा प्रणाली पर भरोसे में कमी का असर शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के स्तर को बुरी तरह प्रभावित करता है।

पढ़ाना और पढ़ना इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके।

परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और मार्कशीट तैयार करना शामिल है।

भारत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली में एकल-मूल्यांकन की प्रणाली है। यह केवल छात्रों की रटने की क्षमता का परीक्षण करती है और उनकी वास्तविक सीखने और समझ को नहीं मापती है।

यह छात्रों पर बहुत अधिक दबाव डालती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को लंबे घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे उनमें मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है।

यह छात्रों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है। धनी और गरीब छात्रों के पास परीक्षाओं की तैयारी के लिए समान संसाधन नहीं होते हैं।

इन खामियों को दूर करने के लिए, भारत में परीक्षा प्रणाली में परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को अधिक समय दिया जाना चाहिए। इससे छात्रों पर दबाव कम होगा और वे अधिक आसाम से परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे।

परीक्षा प्रणाली छात्रों की रचनात्मकता और समस्या-समाधान

## इस भ्रम को तोड़ना ही होगा



डॉ. रामावतार शर्मा

आजकल हम दख रह ह कि सामान्य जन के वार्तालाप और राजनीतिक भाषणों में विकास की बातें अर्थात् रूप से की जा रही हैं मानों देश के हर घर में संपन्नता का साम्राज्य हो गया हो। अब सरकार और लोग यदि सपनों में रहना चाहते हैं तो यह उनका अपना निर्णय है, उनका अधिकार है कि वे ऐसा करते हैं। पर सपने के पार की बालिका चलाने और नौकरी पाने का एक ज्यदा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यह जानना होगा कि यह विकास किस दिशा में हो रहा है।

संघारणीय विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) ही वास्तविक विकास होता है जिसमें वर्तमान में उपभोग करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को

सुरक्षित रखा जाए। यदि हमने आज के अल्पकालीन विकास के लिए सारे संसाधन इस प्रकार से काम में ले लिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ खास बचा ही नहीं तो यह विकास नहीं हमारा प्रभ है। विकास का मतलब मात्र सड़कें, पुल, रेल मार्ग, बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाना ही नहीं होता है। उपरोक्त निर्मितियाँ आवश्यक हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है परंतु यह सारा काम एक संतुलन के तहत होना चाहिए। यदि धरती पर शांति नहीं होगी, संपन्नता हर योग्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, व्यक्तिगत सम्मान नहीं होगा तो सारी भौतिक सुविधाएँ बेमानी हो जाएंगी। चूंकि विकास एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है तो इस बात पर हमेशा जागरूकता रखनी होगी कि यह संघारणीय है या अवनवीन (अनसस्टेनेबल) है। यदि जनता इस बारे में जागरूक नहीं है तो अल्पकाल की सुविधाओं की अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत सहित

एशियाई देशों में व्यक्ति की औकात उसके कार्य से देखी जाती है जैसा कि मध्यप्रदेश के एक जिलाधिकारी द्वारा एक ट्रक ड्राइवर के साथ कटू व्यवहार से स्पष्ट होता है। कार्य के अनुसार जिलाधिकारी एवं ट्रक ड्राइवर दोनों का अपने स्थान पर महत्व होता है और देश के नागरिक को हने नाते दोनों ही सम्मान के अधिकारी हैं परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? सामाजिक सम्मान नहीं मिलने के फलस्वरूप ही देश का श्रमिक वर्ग गैर जिम्मेदार होता जाता है। देश चाहे कितना ही विकास कर ले पर यदि इससे प्रति व्यक्ति कार्य के अनुसार आम नहीं बढ़ती, लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता, शिशु मृत्यु दर कम नहीं होती और बालक-बालिकाएँ स्कूल शिक्षा से वंचित रहते हैं तो यह विकास एक तरफा होगा जिसमें आम लोगों की कीमत पर धनी और धनी होते जायेंगे और सबल निबल के बीच एक खतरनाक तरीके से बढ़ती जाएगी। आर्थिक विकास यदि सामाजिक विघटन, पर्यावरण को हानि और घन संपदा के एकरतफा प्रवाह के साथ होता

कौशल का मूल्यांकन करने में विफल रहती है। यह छात्रों को केवल एक ही सही उत्तर वाले प्रश्नों को हल करने के लिए प्रशिक्षित करती है, जो वास्तविक दुनिया में अक्सर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है।

स्मृति पर अत्यधिक जोर: परीक्षाओं में अनुप्रयोग, विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच आदि जैसे उच्च-स्तरीय कौशलों के बजाय केवल रटने की क्षमता और स्मृति का परीक्षण किया जाता है। समझने में कमी: यह शिक्षण प्रथाओं को छात्रों को वास्तव में अवधारणाओं को समझने के बजाय सामग्री को याद करने पर केंद्रित करती है।

अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि परीक्षा बोर्ड केवल रटने की क्षमता को महत्व देते हैं। इसलिए शिक्षक भी छात्रों की बेहतर सोच विकसित करने की जगह प्रश्नों के उत्तर याद करने और अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करते हैं।

ऐसे कई मौके आए हैं जब हम प्रश्न पत्रों में भाषा और समझ से जुड़ी गंभीर गलतियाँ, विषय से अलग प्रश्न और ऐसे प्रश्न देते हैं जो उच्च शिक्षा का परीक्षण नहीं करते हैं।

परीक्षाओं को अधिक बहुआयामी बनाया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होने चाहिए, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और लंबे उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए, शिक्षा समूहों के मुद्दे पर मानक तय किए जा सकते हैं और मूल्यांकन में सावधानी के लिए नियम लागू जा सकते हैं। इससे छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का आकलन किया जा सकेगा।

मल्टी-मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाए। छात्रों का मूल्यांकन

केवल एक परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी कक्षा प्रदर्शन, परियोजना कार्य, शोध कार्य, और अन्य गतिविधियों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया को जानने का अधिकार होना चाहिए ! मूल्यांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष होना चाहिए।

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच लापरवाही से होती है और छात्रों को मिलने वाले टोटल उनके वास्तविक शिक्षा के स्तर को नहीं दिखाते हैं।

गोपनीयता और समान मानक किसी भी अच्छे परीक्षा की पहचान माने जाते हैं। लेकिन बिना उचित सावधानी बरते, गोपनीयता घोटालों को जन्म देती है।

छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह छात्रों में तनाव और दबाव को कम करने में मदद करे। अभिभावकों को इस मुद्दे पर परीक्षा प्रणाली के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता होगी।

इन परिवर्तनों से भारत में परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा और छात्रों को एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी।

परीक्षा की प्रभावशीलता पर

देशव्यापी बहस चलनी चाहिए।

–प्रो. अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर,

गोरखपुर विश्वविद्यालय, वैदिक

विश्वविद्यालय निंबहारा, निंबाण

विश्वविद्यालय जयपुर,

अध्यक्ष आईएसएलएस, प्रिंसिडेंट

सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपुर

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग मतदाताओं के समर्थन से सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है तो इसका दायित्व अब साधारण मतदाता को अपने हाथ में लेना होगा और सबक सिखाना होगा ऐसा नेताओं को, जो उनके साथ समय-समय पर विश्वास घात करते हुए पाला बदलने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

दूसरे के साथ मिलने की जो कार्रवाई अभी की है, वैसा उदाहरण बहुत नहीं देखने को मिलता है। कैसे किसी की अंतरात्मा गवाही दे सकती है कि कल तक जिसको कोस रहे हों, और विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हों, आज उन्हीं के साथ मंच साझा करके चुनाव प्रचार करें और जिनके साथ अब तक सरकार चला रहे थे, उन्हीं को बड़ा बुरा करना प्रारंभ कर दें।

संयोग से नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने का काम भी तभी किया गया जब 2 दिन पूर्व ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि इस दिन भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। गणतंत्र का अर्थ ही यह है कि जनसाधारण की सत्ता सर्वोच्च है।

आजकल जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसमें जनसाधारण की भूमिका केवल पांच साल में एक बार वोट देने तक सीमित हो गई। जो लोग चुने जाते हैं, वे सिद्धांतों को तर्क में रखकर अवसरवादिता की पराकाष्ठा करते हुए पाला बदलते रहते हैं। ऐसा करके हम गणतंत्र की धारणा को ही नकारने की बात कर रहे हैं।

समय आ गया है, जब ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें एक बार कोई दल किसी दल/गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए और यदि वह अगले चुनाव से पूर्व ही किसी अन्य दल के साथ मिल जाने तो उसकी मान्यता निलंबित रहे अथवा उस दल के सभी निर्वाचित सदस्यों को सदस्यता समाप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नेतागण गिरगिट की तरह रंग बदलते ही रहेंगे यानि पाला बदलते रहेंगे।

ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार न इधर के रहेंगे ना उधर के और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हाशिये पर धकेल देगी। इस प्रकार के नेताओं को सबक सिखाने का काम केवल जनता ही कर सकती है। अब उसे यह अधिकार काम में लेना ही चाहिए।

नीतीश कुमार की बार-बार पाला बदलने की प्रवृत्ति को बहाल देने में भारतीय जनता पार्टी एवं उनके नेताओं ने भी पूरा सहयोग किया है और उसका भी उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। जो नीतीश कुमार, मोदी समेत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक मंच से कोष रहे थे, अब उन्हीं से समझौता करके अपने साथ पास में मंच पर बिठाकर कैसा अनुभव भाजपा के नेताओं को होता होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लगता है, राजनीति में अब किसी भी प्रकार की सिद्धांति का मत करना बेमानी हो गया है।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग मतदाताओं के समर्थन से सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है तो इसका दायित्व अब साधारण मतदाता को अपने हाथ में लेना होगा और सबक सिखाना होगा ऐसा नेताओं को, जो उनके साथ समय-समय पर विश्वास घात करते हुए पाला बदलने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

पाठकों को शायद पता हो कि गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा राष्ट्र, जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित है।

नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व तीन बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुके हैं और तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके थे। नीतीश कुमार के बार-बार गठबंधन को रद्द करने से उनकी छवि को निश्चित रूप से धक्का लगा है। वह इंडिया ब्रॉक या विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक के रूप में भूमिका निभा रहे थे और रातों रात इन्होंने एन डी ए से समझौता कर लिया। देश में ऐसा कोई भी नेता शायद नहीं होगा जिसने 9 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली होगी। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने जिस दल के साथ गठबंधन किया उसे तीन बार तोड़ कर पुनः उसके साथ समझौता किया हो। नीतीश कुमार का यह कृत्य देश की राजनीति में काले अश्वत्थ के रूप में ही देखा जाएगा।

आशा की जाना चाहिए कि बार बार पाला बदलने की यह अनिष्ट घटना ही होगी। आगामी चुनावों में नीतीश कुमार को बुरी तरह परख करके ही यह संदेश दिया जा सकता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं को पसंद नहीं किया जाता। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को तेजी से रंग बदलते देखकर तो गिरगिट की भी शर्म आ जाए।

–अतिथि सम्पादक,  
राजेन्द्र भागवत  
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

## मीठी भुगड़ी के हिस्से आ रही कड़वी यादें, तालाब निगल रहा बेरों की बोरेटी

बीकानेर। यहां से बाहर प्रवास करने वाले यहां के वाशिंग में भुजिया, पापड़, सूखी सब्जियों के अलावा सूखे बेर यानी भुगड़ी का भी खासा क्रेज रहा है। सुजानदेसर रोड पर सालसमनाथ जी के धोरे के आसपास की बाडियां रियासतकाल से ही मीठे बेर एवं भुगड़ी के उत्पादन लिए प्रसिद्ध रहे हैं। हालांकि, करीब तीन दशक से इस क्षेत्र में पैदा होने वाली यह निहामत अब जमीदोर होने की स्थिति में है। गंगाशहर, भीनासर, किसमोदेसर एवं आसपास के क्षेत्र का धरेलू एवं बरसाती पानी चांदमलजी के बाग एवं सड़क के दूसरी तरफ दर्जनों बीघा में पानी फूल जाने से ही बेर की सैकड़ों बोेटियां यानी झाडियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।

कई पीढ़ि यों ने अपने खून-पसीने सींचकर बेर की इन झाडियों और पेड़ों को लगाया था। हालांकि आर्युआईडीपी के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर बनी योजना से पानी गोचर भूमि में जाने लगा है, लेकिन अभी भी सड़क के दूसरी तरफ ब्रासमणों के मोहल्ले में दर्जनों बीघा क्षेत्र में गंदा पानी सपना हुआ है। इसने झाडियों को निगल लिया है। अब गिनी-चुनी बाडियों में ही बेर की झाडिया बची है। उन पर लगने वाले बेरों की मात्रा भी इतनी कम होती है कि इसके साथ-साथ स्थानीय बाजार में ही विक्रि जाते हैं। पीढ़ि यों से इस काम में लगे परिवार के हरिराम माली 30 – 35 वर्ष पूर्व की स्थिति को याद

करते हैं, जब यहां आसपास की बाडियों में सैकड़ों बेरों की झाडियां होती थीं और उनसे सैकड़ों किलो बेर रोजाना होते थे। फिर इन बेरों की छंटाई होती थी। जो ज्यादा गीले होते थे उनको कई दिनों तक धूप में भुगड़ी बनने के लिए सुखाया जाता था। बेबी, इन्ना आदि ने बताया कि महिलाएं उस दौर में झाडियों से नीचे गिरे बेर चुगने के लिए बड़ी संख्या में बाडियों में जाती थीं और उनके लिए यह रोजगार का भी अच्छा साधन था।

गंगाशहर बाजार के पुराने दुकानदारों में शुमार सुरेंद्र कुमार गोलछा के मुताबिक, करीब 25 – 30 वर्ष पहले दुकान में भुगड़ी की खपत सालाना एक किंवदंतल तक हो जाती थी, जो अब घटकर पांच – सात किलो ही रह गई है। पहले यहां से जाने वाले स्वामी कोलकाता, असम, दिल्ली, गुजरात आदि स्थानों पर भुगड़ी ले जाते थे। फिलहाल, एक किलो बेर की कीमत करीब 40 रुपए है, जबकि भुगड़ी अस्सी से सौ रुपए प्रति किलो तक मिलती है। हालांकि, यह स्थानीय खपत को भी पूरा नहीं कर पाती। भुगड़ी के लिए तो बेर बचते ही नहीं। महानगरों में रहने वाले लोग निकटजनों के लिए बीकानेर की नमकीन के साथ भुगड़ी अवश्य ले जाते थे। अब इसका क्रेज और उत्पादन दोनों ही कम हो गया है। आज की किशोर-युवा पीढ 1 तो भुगड़ी के स्वाद से ही अनजान है।

## नाल में 1 फरवरी को होगा एयर शो, आसमान में दिखेंगे सूर्यकिरण प्लेन के करतब

बीकानेर। भारतीय वायु सेना के एयर शो की बीकानेर के नाल स्टेशन में तैयारियां चल रही हैं। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के प्लेन शामिल होंगे। लाल रंग के इन विमानों पर सफेद पट्टी बनी होती है। जो आसमान में कलाबाजियां करते बेहद खूबसूरत दिखते हैं। आमजन 1 फरवरी को बीकानेर में उतरे पराशुर्ट्स भी साहसिक प्रदर्शक करेंगे। अभी 12 से 14 जनवरी तक मुम्बई में तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन किया गया था। इसमें वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्टले टीम भी शामिल हुई थी।

नाल स्टेशन में सुबह 8.30 बजे से आमजन को एयरशो देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसमें पहचान

दस्तावेज देखकर प्रवेश मिलेगा। मोबाइल व कैमरा साथ नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही खाने-पीने का किसी तरह का सामान नहीं ले जा सकते हैं। एयरशो 11 बजे शुरू हो जाएगा।

एयरशो को लेकर वायुसेना के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालयों से साहसिक आयुक्त कार्यालयों के साथ पिछले दिनों बैठक भी की थी। इसमें नाल और आस-पास की एक-दो किलोमीटर की परिधि में कोई भी मृत पशु और कचरा आदि खु